



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 4, 2013/चैत्र 14, 1935

No. 56।

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 4, 2013/CHAITRA 14, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2013

विषय : ई यू, यू एस ए तथा कोरिया जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "मिथायलीन क्लोराइड" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 14/19/2012-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार मै० कैमप्लास्ट सेनमार लि० तथा मै० गुजरात फ्लोरोकैमिकल्स लि० (जिन्हें एतदपश्चात "याचिकाकर्ता कंपनियाँ" अथवा "आवेदक" कहा गया है) ने ई यू, यू एस ए तथा कोरिया जन.गण. (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित मिथायलीन क्लोराइड (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। मै० कैमप्लास्ट सेनमार लि० और मै० गुजरात फ्लोरोकैमिकल्स लि० ने संगत सूचना प्रदान की है।

विचाराधीन उत्पाद

2. मौजूदा याचिका और प्रस्तावित जाँच में विचाराधीन उत्पाद "मिथायलीन क्लोराइड" है जिसे 'डाइक्लोरोमीथेन' तथा "मिथायलीन डायक्लोराइड" (एम डी सी) के नाम से भी जाना जाता है। मिथायलीन क्लोराइड एक कार्बनिक सम्मिश्रण है जिसका आण्विक सूत्र CH_2Cl_2 है। यह एक

रंगहीन तरल है जिसकी सुगंध ईंधर जैसी होती है और इसका प्रयोग मुख्यतः विलायक के रूप में होता है। प्रयोग की अधिकांश दशाओं में यह अनिवार्यतः अज्जवलनशील होता है लेकिन अत्यधिक गर्म किए जाने पर जल सकता है। अत्यधिक तापमान पर मिथायलीन क्लोरोइड अपघटित हो सकता है जिससे विषेली गैसें उत्पन्न होती हैं। यह विभिन्न विलायकों के साथ पूर्णतः मिश्रणीय है। एम डी सी एक विलायक है और इसका इस्तेमाल पॉलीकार्बोनेट तथा फेनोलिक रेजिन्स, रेयॉन यार्न, भेषजों, एग्रो तथा सुगंधों के विनिर्माण में किया जाता है। खाद्य वसा, कोको, मक्खन तथा एसेंसेज हेतु इसका इस्तेमाल निष्कर्षक के रूप में भी किया जाता है। मिथायलीन क्लोरोइड के उत्पादन हेतु दो प्रौद्योगिकियाँ मौजूद हैं—मीथेन रूट तथा मीथेनॉल रूट। इन दोनों रूटों के माध्यम से उत्पादित उत्पाद के तकनीकी विनिर्देशन अनिवार्यतः समान होते हैं। मिथायलीन क्लोरोइड सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 (कार्बनिक रसायन) के अंतर्गत सीमाशुल्क उपशीर्ष 29031200 के तहत वर्गीकृत है। यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से प्रस्तावित जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तुएँ

3. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु जिसका निर्यात संबद्ध देश द्वारा भारत को किया जाता है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित मिथायलीन क्लोरोइड वास्तविक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय है। उपभोक्ता इन दोनों उत्पादों को एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग में ला सकते हैं। ये दोनों उत्पाद तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए इन्हें पाटनरोधी नियमों के तहत "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग एवं स्थिति

4. यह नोट किया गया है कि कुल भारतीय उत्पादन में आवेदकों का हिस्सा 50% से अधिक है और चूँकि समर्थकों सहित याचिकाकर्ताओं का उत्पादन, भारतीय उत्पादन का 83% है अतः भारत में उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन में याचिकाकर्ताओं का एक प्रमुख हिस्सा है। यह भी नोट किया गया है कि किसी भी याचिकाकर्ता ने न तो विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वे विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित हैं। अतः यह निर्धारित किया गया है कि यह आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है और आवेदन पाटनरोधी नियम के नियम 5 के तहत अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसके अलावा, आवेदक पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) के संदर्भ में "घरेलू उद्योग" है।

संबद्ध देश

5. वर्तमान जाँच में शामिल देश ई यू अमरीका तथा कोरिया जन.गण. है।

सामान्य मूल्य

6. याचिकाकर्त्ताओं ने निवेदन किया है कि संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की कीमत के संबंध में सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया था और उन्होंने आई सी आई एस एल ओ आर प्राइजिंग रिपोर्ट से यूरोप तथा अमरीका में प्रचलित कीमत संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है। कोरिया जन. गण के मामले में याचिकाकर्त्ताओं ने सामान्य मूल्यों का परिकलन किया था। याचिकाकर्त्ताओं ने कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, घरेलू उद्योग के सर्वोत्तम खपत मानक तथा समुचित लाभ मार्जिन पर विचार करके सभी संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य का भी परिकलन किया है। खुली/पैक न की गई तथा पैक की गई सामग्री की लागतों एवं कीमतों में अत्यधिक अंतर को देखते हुए दोनों प्रकारों के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। प्राधिकारी ने आवेदकों के दावे की जांच की और यह नोट किया है कि संबद्ध देशों/क्षेत्र में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं।

निर्यात कीमत

7. आवेदकों ने भारत में आयातों की मात्रा एवं मूल्य का आकलन करने के लिए डी जी सी आइ एंड एस टी बाई टी आंकड़ों के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्यात कीमत का दावा किया है। उत्पाद के खुले तथा पैक स्वरूप के लिए अलग-अलग निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा व्यय तथा बैंक प्रभारों के आधार पर कीमत समायोजन किया गया है। संबद्ध देशों/क्षेत्र में संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं।

पाटन मार्जिन

8. आवेदक ने पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए इसका पर्याप्त प्रमाण दिया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य निवल निर्यात मूल्यों से अधिक है जो प्रथम दृष्ट्या यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

क्षति एवं संबंधित कारण

9. आवेदकों ने दावा किया है कि उन्हें हानियों, माल सूची में वृद्धि, निवेश की गई पूंजी पर लाभ अर्जन तथा नकद लाभ में गिरावट तथा प्रचालन निष्पादन में पतन के कारण क्षति पहुँची है। आवेदक ने निग्रहण, कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री के कारण प्रतिकूल कीमत प्रमाणों का भी दावा किया है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि यह क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात के पाटन के कारण हुई। प्राधिकारी वा विचार है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात द्वारा आवेदकों को क्षति पहुँचने के पर्याप्त प्रमाण हैं अतः पाटनरोधी जांच आरंभ करना न्यायोचित होगा।

जांच की शुरुआत

10. प्राधिकारी ने पाया कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की और वहाँ से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को 'क्षति' और पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या प्रमाण है। प्राधिकारी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, जिसके अधिरोपण से घरेलू उद्योग की क्षतिपूर्ति होगी, की सिफारिश करने हेतु कथित पाटन और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति हेतु एतद्वारा पाटनरोधी नियमों के नियम 5 के अनुसार जांच आरंभ करते हैं।

जांच की अवधि

11. वर्तमान जांच हेतु जांच अवधि 1 जनवरी, 2012 से दिसम्बर 2012 होगी। तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2009 - मार्च, 2010, अप्रैल 2010 - मार्च, 2011, अप्रैल 2011 से मार्च 2012 और जांच की अवधि (पी ओ आई) शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

12. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देश की सरकार को, भारत में स्थित उनके राजदूतावासों के जरिए संबंधित आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योगों को निर्धारित स्वरूप में तथा निर्धारित फार्म में समर्त जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए अलग-अलग सूचित किया जा रहा है। अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संबंधित सूचना नीचे निर्धारित समय के भीतर निम्नलिखित को प्रस्तुत कर सकता है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा सं0 240, उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110107

समय-सीमा

13. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन (चालीस दिन) के भीतर पहुँच जानी चाहिए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण में, रिकॉर्ड में 'उपलब्ध तथ्यों' के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

14. पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(1) के अनुसार प्रदान की गई गोपनीय सूचना हेतु पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के संदर्भ में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा एक गोपनीय तथा अगोपनीय सार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। गोपनीय सूचना का अगोपनीय रूपान्तर या अगोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण युक्त होना चाहिए जिससे कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना की एक सार्थक समझ प्रदान की जा सके। यदि सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विचार में ऐसी सूचना का सारांश नहीं बनाया जा सकता है तो उसके कारणों का विवरण प्रदान करना अपेक्षित होगा।

यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता हेतु अनुरोध प्राधिकृत नहीं है अथवा सूचना प्रदायक या तो सूचना सार्वजनिक करने को अनिच्छुक है या सामान्य अथवा संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत नहीं कर रहा है तो वे इस तरह की सूचना का अवहेलना कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

15. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्षों के अगोपनीय रूपान्तर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

16. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने से मना करता है अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर सूचना प्रस्तुत नहीं करता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2013

**Subject : Initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of
“Methylene Chloride” originating in or exported from EU, USA and Korea
RP.**

F. No. 14/19/2012-DGAD.—M/s. Chemplast Sanmar Ltd. and M/s. Gujarat Fluorochemicals Ltd., (hereinafter referred to as 'petitioner companies' or "the applicants") has filed an application (also referred to as petition) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping

Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of Methylene Chloride (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from EU, USA and Korea RP (hereinafter also referred to as the subject countries). M/s Chemplast Sanmar Ltd. and M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd. have provided relevant information.

Product under consideration

2. The product under consideration in the present petition and proposed investigation is "Methylene Chloride" also known as "Dichloromethane" and "Methylene Dichloride" (MDC). Methylene chloride is an organic compound with molecular formula CH_2Cl_2 . It is a colorless liquid with sweetish ether-like odor, and is used as a solvent, predominantly. It is essentially non-flammable under most conditions of use, however, can burn if strongly heated. Methylene chloride may decompose at high temperatures forming toxic gases. It is completely miscible with a variety of solvents. MDC is a solvent and is used in the manufacturing of polycarbonate and phenolic resins, rayon yarn, pharmaceuticals, agro and fragrance. It is also used as an extractant for edible fats, cocoa, butter and essences. There are two technologies for production of Methylene Chloride - Methane route and Methanol route. The product produced through the two routes has essentially similar technical specifications. Methylene Chloride is classified under Chapter 29 (Organic Chemical) of the Customs Tariff Act under customs subheading 29031200. The Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the proposed investigation

Like Articles

3. The applicant has claimed that the subject goods, which are exported from subject country into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. Methylene Chloride produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants in India is being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic Industry & Standing

4. It is noted that the Applicants account for more than 50% of the total Indian production and production by the petitioners constitute a major proportion in total production of the like product produced in India, as production of the petitioners including supporters constitute 83% of Indian production. It is also noted that none of petitioners have imported the product under consideration, nor they are related to an importer or exporter of the product under consideration. It is thus determined that the application has been made by or on behalf of the domestic industry and the

application satisfies the requirements of 'standing' under Rule 5 of the AD Rules. Further, the Applicants constitute 'Domestic Industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

5. The countries involved in the present investigation are EU, USA and Korea RP.

Normal value

6. The Petitioners have submitted that efforts were made to get information/evidence of price of subject goods in the domestic market of subject countries and they have furnished the information of prices prevailing in Europe and USA from ICIS LOR Pricing report. In respect of Korea RP, petitioners had constructed the normal values. The petitioners have also constructed normal value for all subject countries taking into account international raw material price, best consumption norm of domestic industry and reasonable profit margin. In view of significant difference in the costs and prices of loose/unpacked and packed material, the normal value has been determined separately for the two forms. The Authority examined the claim of the applicants and notes that there is sufficient *prima facie* evidence of normal value of the subject goods in the subject countries/territory.

Export Price

7. The applicants have claimed export price for product under consideration based on DGCI&S T by T data to assess the volume and value of imports in India. Export price has been separately determined for loose and packed form of the product. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight expenses and bank charges. There is sufficient *prima facie* evidence of export price of the subject goods in the subject countries/territory.

Dumping Margin

8. The applicant has provided sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, *prima-facie* indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries are being dumped, to justify initiation of an antidumping investigation.

Injury and Causal Link

9. The applicants have claimed that they have suffered material injury by way of losses, increase in inventories, decline in return on capital employed and cash profits, and deterioration in their operating performance. The applicant has also claimed adverse price effects as evidenced by price suppression, price undercutting and price underselling. The applicants have also claimed that the injury has been caused due to the dumped imports of subject goods from subject countries. The Authority considers that there is sufficient evidence of the 'injury' being suffered by the applicants caused by dumped imports of subject goods from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

Initiation of Investigations

10. The Authority finds that sufficient *prima facie* evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link between the dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Period of Investigation

11. The period of investigation for the present investigation is proposed from 1st January 2012 to December 2012. However, the injury investigation period will cover the periods April 2009-March 2010, April 2010-March 2011, April 2011 to March 2012 and the Period of Investigation (POI).

Submission of information

12. The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
Room No.240, Udyog Bhawan,
New Delhi -110107.

Time limit

13. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

Submission of Information on Non-Confidential basis

14. All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7 (2) of the AD Rules for the confidential information provided as per Rule 7 (1) of the AD Rules. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties.

If in the opinion of the party providing information, such information is not susceptible to summary; a statement of reason thereof is required to be provided.

Notwithstanding anything contained in para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.

Inspection of Public File

15. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

16. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority